

DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं का सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार करने हेतु एजेन्सियों के चयन के लिए ई-टेंडर के माध्यम से कलस्टर-3 हेतु प्रकाशित निविदा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का थर्ड पार्टी के द्वारा किये गये तकनीकी मूल्यांकन के परीक्षण के पश्चात वित्तीय निविदा डाउनलोड/खोले जाने एवं एजेन्सियों के चयन हेतु मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति की दिनांक 13.12.2018 की बैठक का कार्यवृत्त

DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कलस्टर-3 के 10 शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सियों के चयन किये जाने के लिए दिनांक 03.09.2018 को ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड/प्रकाशित कलस्टर आधारित 03 निविदायें- RFP No.- 3342/241/NULM/Teen/2017-18(SUSV-Tender) को दिनांक 09.10.2018 को ई-टेंडर से निविदा डाउनलोड/खोली गई है।

उक्त कलस्टर-3 में प्राप्त 6 निविदाओं को तकनीकी मूल्यांकन में अर्ह पाया गया, जिनको निविदा समिति के निर्णय के क्रम में थर्ड पार्टी आर0सी0यू0ई0एस0 लखनऊ से मूल्यांकन कराया गया। थर्ड पार्टी आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ द्वारा पत्र दिनांक 12.11.2018 के द्वारा एजेन्सियों की तकनीकी मूल्यांकन शीट उपलब्ध कराई गई, जिसको दिनांक 30.11.2018 को आहूत निविदा समिति के बैठक में पुनर्परीक्षण किया गया, जिसमें कलस्टर-3 में 5 निविदाओं यथा-KDS Services Pvt. Ltd., Tech Creative Solution, LRM Consultant, Karvy Data Management Services Limited, DMG Consulting Pvt. Ltd. को वित्तीय निविदा डाउनलोड/खोले जाने हेतु अर्ह पाया।

कलस्टर-3 के 10 शहरों यथा- मुगलसराय (जनपद-चंदौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोडां, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुल्तानपुर, एवं देवरिया हेतु एजेन्सियों से प्राप्त वित्तीय निविदा का विवरण निम्नवत है -

क्र. सं.	एजेन्सी का नाम	वित्तीय निविदा रु0 प्रति वेन्डर की दर से		वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात एजेन्सियों की स्थिति
		अंको में	शब्दों में	
1	KDS Services Pvt. Ltd.	Rs.143/-	One Hundred & Forty Three only	L-1
2	Tech Creative Solution	Rs.185/-	One Hundred & Eighty Five only	L-2
3	LRM Consultant	Rs.310/-	Three Hundred & Ten only	L-3
4	Karvy Data Management Services Limited	Rs.311/-	Three Hundred & Eleven only	L-4
5	DMG Consulting Pvt. Ltd.	Rs.1103.77/-	One Thousand One Hundred Three & Seventy Paise	L-5

कलस्टर-3 के उक्त 10 शहरों हेतु KDS Services Pvt. Ltd. की प्रति वेन्डर रु. 143/- को न्यूनतम पाया गया।

निविदा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कलस्टर-3 हेतु KDS Services Pvt. Ltd. की दर प्रति वेन्डर रु. 143/- को अनुमोदित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

कलस्टर-3			
क्र. सं.	शहर का नाम	दर रु. प्रति वेन्डर	एजेन्सी का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण
1	मुगलसराय (जनपद-चंदौली)	Rs.143/-	Director, KDS Services Pvt. Ltd. Address- 011-012, Second Floor, Parsvanath Planet Plaza, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-10, U.P. Mobile- 9369669696, 9044881122 Tel/Fax- 0522-2720777 E-mail: info@kdsgroup.com
2	गाजीपुर	Rs.143/-	
3	आजमगढ़	Rs.143/-	
4	बलिया	Rs.143/-	
5	बस्ती	Rs.143/-	
6	बहराइच	Rs.143/-	
7	गोडां	Rs.143/-	
8	अकबरपुर (अम्बेडकर नगर)	Rs.143/-	

9	सुल्तानपुर,	Rs.143/-
10	देवरिया	Rs.143/-

निविदा के अनुसार उक्त दरों में समस्त व्यय/टैक्स सम्मिलित हैं, GST/Service Tax अलग से देय होगा।

उक्त चयनित एजेन्सी द्वारा सी0एम0एम0यू0-डूडा के अनुश्रवण में DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक सर्वे, आधार न0, मोबाईल न0, एम0आई0एस0, जी0आई0एस0 (City Level Mapping, Vendor Location Level Mapping, Capturing Photo and biometric identity of Street vendors, Preparing Registration certificates & ID cards for Street vendors, Preparing MIS Software, Vendor Census Survey, Preparing de-duplication software, Linkages with Aadhar no.) वेडिंग जोन/नान वेडिंग जोन के निर्धारण, पथ विक्रेताओं के वेडिंग प्रमाणपत्र, आई कार्ड तैयार करना, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान आदि तैयार करने के सभी कार्य भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014, उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता योजना, 08.09.2016, उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता नियामावली, 10.05.2017 एवं निविदा के Terms of Reference (ToR) में दिये गये कार्यों के अनुसार समस्त कार्यों को समयबद्ध रूप से किया जायेगा। निविदा के अनुसार उक्त सभी कार्य 26 माह में पूर्ण किये जाने हैं।

उक्त सभी शहरों के सी0एम0एम0यू0-डूडा को निर्देशित किया जाता है कि कार्यवृत्त जारी होने के 15 कार्य दिवसों के अन्दर एजेन्सियों को कार्यदेश जारी करते हुए अगले 15 कार्य दिवसों में अनुबंध हस्ताक्षरित करते हुए नियमानुसार कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि


(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक


राज्य शहरी आजीविका मिशन-सूडा, उ0प्र0
सूडा भवन, 23, सेक्टर 7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-206027

पत्रांक-9791/241/NULM/लेन/2001 SUSV टेण्डर

दिनांक-22/01/2019

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, (यू0पी0ए0) आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा- चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोडां, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, एवं देवरिया।
5. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, शहर मिशन प्रबंधन इकाई- मुगलसराय (जनपद-चंदौली), गाजीपुर, आजमगढ, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोडां, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुल्तानपुर, एवं देवरिया।
6. परियोजना अधिकारी, डूडा- चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोडां, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, एवं देवरिया।
7. चयनित एजेन्सी KDS Services Pvt. Ltd. समय से कार्य प्रारम्भ करने हेतु।
8. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

ToR & Performance Security Form **(Bank Guarantee) for Cluster - 3**

SURVEY OF STREET VENDORS, PREPARATION OF CITY STREET VENDING PLAN (CSVP) AND DETAILED IMPLEMENTATION PLAN (DIP) FOR INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT PROJECTS Etc. UNDER SUPPORT TO URBAN STREET VENDORS (SUSV) COMPONENT OF DEENDAYAL ANTYODAYA YOJANA-NATIONAL URBAN LIVELIHOOD MISSION (DAY-NULM) FOR 10 CITIES/ULB OF UTTAR PRADESH

(RFP in accordance with Amended Operational guidelines of SUSV component of National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) issued by MoHUPA, Govt of Uttar Pradesh vide O.M. No. K-14012/14/2016-UPA/FTS-163203 dated 18.02.2016 based on Street Vendors (Protection of Livelihoods and Regulation of Street Vending) Act 2014.

Annexure C: Terms of Reference

1 Project Background

The recently launched Deendayal Antyodaya Yojna-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) aims to promote sustainable development of the large informal and unorganized workforce in the urban areas. DAY-NULM urges special attention on street vendors as an occupational group in the informal sector and requires that interventions be designed for this group so as to improve their quality of life. It is estimated that in several cities street vendors count for about 2 percent of the population. Women constitute a large segment of these street vendors in almost every city. Street vending is not only a source of self-employment to the poor in cities and towns but also a means to provide "affordable" as well as "convenient" services to a majority of the urban population. With this background, the aim of this exercise is to support City Mission Management Unit/DUDA/Nagar Palika Parishad for Survey of Street Vendors, Preparation of City Street Vending Plans and Detail Implementation Plan for Infrastructure improvement projects. The brief description of the tasks to be undertaken in this project is listed as below:

- 1.1 All activities shall be done in accordance with the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vending) Act 2014, UP Street Vendors scheme 2016 and UP Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules 2017 and operational Guidelines of Support to Urban Street Vendors (SUSV) under DAY-NULM issued by MoHUPA, Government of India and directions issued by the State Government from time to time.**

2 Survey & Identification of Street Vendors

The first and foremost task is to identify and profile the street vendors. Street vendors in City have to be identified and estimated and numbered at ground level for Biometric process. Vendors need to be classified under three major categories:

Stationary: Those who carry out vending on a regular basis at a specific location, e.g. those occupying space on the pavements or other public places and/or private areas either open/covered (with implicit or explicit consent) of the authorities, and operating on usufruct rights

Peripatetic/wandering: Those who carry out vending on foot and sell their goods and services and include those who carry baskets on their head/slung on their shoulders and those who sell their goods on pushcarts

Mobile: Those who move from place to place vending their goods or services on own vehicles like bicycle or mobile units on wheels, motorized and manually driven, as well as in moving buses, local trains etc.

While categorizing the street vendor based on the above, care may be taken to ensure that the unique characteristic that differentiates a street vendor from other types of vendors, i.e., that they complete their transactions by the end of the day or part of the day thereof, following which they will wrap up their wares and remove them from the spot till the next time of vending.

During the identification period, wide publicity of the event will be taken up in the ULB through banners and mike announcement to ensure that those members not covered by the enumerator during the field canvassing of questionnaires can physically come to the Municipality and get registered.

Once the vendor list is finalized, the following tasks have to be undertaken:

1. Identification of areas where street vendors have been profiled which may be classified as restriction-free, restricted and prohibited vending zones based on set criteria. These criteria may be determined in advance by the ULB in accordance with the broad framework given by the government in the National Street Vending Policy 2009, the Street Vendors' (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act 2014, the Uttar Pradesh Scheme for Street Vendors 2016 and the Uttar Pradesh Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017.
2. Identification of existing natural and emerging markets for considering the possibility of developing them into regular markets and vending zones in a PPP mode for the vendors.
3. Identification of vending zones operating on time-sharing basis as well as weekend market zones
4. Work out the holding capacity of the vending zones identified
5. Work out procedure of allotment of spaces for vendors' markets for regular as well as vending on time-sharing basis including the period of validity of the allotment of spaces for the vendors.
6. The survey shall be conducted zone, ward or market wise in the form prescribed in the rules and all the data shall be stored digitally.

3 GIS Base Mapping and Surveys

GIS mapping has to be undertaken at two levels namely City level mapping and vendor level mapping.

3.1 City Level Mapping

The geo-referenced base map of the city shall serve as a foundation for preparing Street Vending Plan where all other thematic maps may be overlaid for spatial analysis. Thus, it shall aid Planners in preparing Vendor Plan. City level GIS mapping has to be done with the help of latest satellite imagery. For that purpose, Procurement of Cartosat II / Quick Bird / World View satellite image from the National Remote Sensing Agency (NRSC) or any other authorized Agency for the project area has to be purchased by the Consultant and it shall be reimbursed by the client.

The following layers have to be created in city level mapping:

1. City/Municipal and ward boundaries
2. Vendors/vending zones will be captured using GPS equipment
3. All water bodies, viz., Stream, creeks, tanks, etc
4. Roads with classification as Arterial /Sub arterial /Slum roads etc
5. Railroads, Other landmarks such as temples, mosques, church etc.

3.2 Vendor Location Level Mapping

The delineation of vendor zonal boundaries has to be done with the full involvement of the vendors and its association, if any. The delineation of boundary will be done in GIS with the help of GPS co-ordinates captured for all the vendors.

This will be based on the division of the zones for restriction-free vending, as well as for vending on restricted basis and areas where vending is prohibited. This activity will take into account existing norms, if any, in the City level, the authenticity of such a division. Existing norms pertaining to the zoning (green, amber and red zoning) will be studied and relevant norms for the city will be worked out.

3.3 Capturing Photo and biometric identity of Street vendors

The following steps have to be followed for capturing photo and bio-metric identity of the vendors:

1. Developing and implementation of user interface to capture photo and biometric identity data
2. Installation or deployment of user interface software in laptops /computers to capture Photo and biometric identity data
3. Store photo and biometric data into database in appropriate format
4. Check and validate stored photo and biometric data.

3.4 Preparing Registration certificates & ID cards for Street vendors

Each vendor surveyed has to be given Registration Certificates & photo ID cards and the steps followed are listed as below:

1. Format preparation for Registration Certificates & ID cards to print
2. Verify the correctness of data
3. Print Street Vendor Registration Certificates & Photo ID cards.

Such identity card and the certificates of vending shall be given to the street vendors after approval and in the manner prescribed by the Competent Authority (Town vending Committee) and ULB/CMMU/DUDA/SULM-SUDA, UP.

3.5 Preparing MIS Software

A data base of all street vendors will be maintained by the ULB. So, Consultant will have to prepare software which helps ULB to maintain all records of vendors in future also. As vendors are mobile, the software should be able to track (based on either present/permanent address or any other criteria) whether the vendor has already been covered and issued an Identity Card. For such purpose, software has to be developed for monitoring after implementation of the street vending Plan to monitor the entire allotment, registration and the whole above process.

3.6 Vendor Census Survey

Consultant has to conduct of survey for identification and enlisting of street vendor and it has to be carried out with trained enumerators in a digital. The survey should preferably be conducted on a whole city basis. Alternatively, the Consultant may also choose to complete the survey in a phased manner, covering one area (ward/ zone/ specified part of city) at a time. In this case, the area identified should be sufficiently large to accommodate mobility of vendors within the area. The survey must cover all street vendors in the area being surveyed. Consultant has to developed methodology for conducting the survey. At a minimum, the survey must include Name, Name of parents, Permanent Address, Present Address, Identity proof (if any), Telephone number (if any), Place of vending, Type of vending activity, Time/Duration of engagement as a vendor, Details of family members, if identified as beneficiary/poor for any of the government schemes like Food Security Act, TPDS, SJSRY, etc (using survey format prescribed in the schemes or rules.

During the survey, the original documents pertaining to present/permanent address proof, especially in the case of migratory population may also be verified so that the Identity Cards issued to the surveyed street vendors can act as sufficient documentation for opening of their bank accounts, getting loans from banks, accessing social security benefits, etc.

Every street vendor to whom the certificate of vending has been issued shall be given an identity card in the prescribed format. A data base of all registered street vendors will be maintained by the Town vending committee. Since the vendors are mobile, the software should be able to track (based on either present/permanent address or any other criteria) whether the vendor has already been covered and issued an Identity Card.

3.7 Preparing de-duplication software

In order to avoid duplication, consultants have to develop de-duplication software and the steps have to be followed are as listed below:

1. Developing and Implementation of de-duplication software to verify captured biometric data.
2. Generate a report for duplicated (bulk) biometric data
3. Allow duplication verification process while capturing biometric data at the later stage.

3.8 Linkages with Aadhar no.

All details recording street vendors surveyed shall be linked with their Aadhar nos positively. If any vendor is not having his Aadhar number. The consultant shall facilitate in enrolment of Aadhar.

4. Preparation of City Street Vending Plan

- (1) The consultant has to prepare city Street vending plan as per the provisions of the Street Vendors (Protection of livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 the Uttar Pradesh (Protection of livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017 and the Uttar Pradesh Scheme for Street Vendors 2016.
- (2) The plan shall be prepared to promote the vocation of street vendors covering the matters contained in the First Schedule of the Act 2014.
- (3) The Street Vending Plan will also take into account the natural markets where sellers and buyers naturally congregate for the sale and purchase of products and services. The Plan will be developed after consultations with Street Vendor's representatives and other relevant stakeholders.
- (4) While preparing the Street Vending Plan, the consultant shall coordinate with the city police, traffic police, planning authority and other local agencies should also devise and promote vendor friendly policies, solutions and strategies to accommodate and facilitate street vending in a manner that is conducive to street vendors and the public at large. This may include policies for traffic management and regulation on market days or at certain times of the day, arrangements for lighting, water, sanitation and waste disposal in street vendor market areas. The ULB may coordinate with planning authorities to develop pro-vending norms and stipulation of vending spaces in new or refurbished roads, markets, office and residential complexes and other public spaces and public infrastructure. This will ensure greater acceptability of Street Vending Plans among the stakeholders.
- (5) The consultant should make every effort to minimize disruption to existing markets while developing the city street vending plan. Accordingly, the plan may be developed in such a manner that no relocation or eviction of street vendors takes place. Re-location of street vendors, if required, must be based on consultation with the affected vendors. Based on the survey findings, the City Street Vending plan may also include a digitized or non-digitized map of vending activities, vending trades and existing markets at ward or zone level.

- (6) **Management Information System** - Street vending Plan has to suggest methods of Monitoring system using MIS software. For such purpose, software has to be developed for monitoring after implementation of the street vending Plan to monitor the entire allotment, registration and the whole above process. This MIS software has to be developed in consultation with the Municipal Corporation.
- (7) The plan for street vending shall be put up to the ULB through CMMU for approval of the State Government.

5. Preparing Detailed Implementation Plan (DIP)

The Consultant has to prepare a Detailed Implementation Plan (DIP) for infrastructure improvement projects which may include improved civic facilities such as paving, water supply, toilets, waste disposal facility, lighting, common storage space, and specialized carts for specific types of trades, temporary sheds and/or parking facilities. The infrastructure requirements for vendors markets will be assessed based on consultations with street vendors and their associations, local agencies and other stakeholders and will be facilitated by the ULB.

The DIP for infrastructure improvement must be prepared only after the street vendor survey and the master plan for the area where the project is located, has been completed. While preparing the DIP, provision for providing specialized carts to the street vendors for specific types of trades such as food vending etc. may be included with a view to improve the hygiene and optimal utilization of space. These carts may be funded through individual loans covered under the SEP component of DAY-NULM

5.1 DIP should contain:

- (i) Project rationale, details of beneficiaries and stakeholders, how it will contribute to improved street vending in the surrounding area, and how it fits within the overall City Street Vending Plan
- (ii) Land ownership details
- (iii) Relocation plan, if any must be supported by a letter of consent from the affected street vendors and/or their association
- (iv) Specific infrastructure improvement project details with costs, including operations and maintenance plan
- (v) Detailed and complete list of beneficiaries who will benefit from the project
- (vi) Safety concerns, if any, relating to fire hazard or other hazards.

DIP for creation of food streets farmers' markets night market and other such specialized/theme based markets may also be developed.

DIP must be submitted to the State Level Project Sanctioning Committee of SULM, UP after approval of City Street Vending Plan (CSVP).

6. Outputs and Deliverables

The following outputs are expected to be delivered in stages

Sr. no.	Deliverable	Copies	Due date
1	Conduct of Survey for Identification and enlisting of Street Vendors	2 set of hard copies & 2 set of soft copies	End of Week 9
2	Bio-metric survey, capturing photographs, preparation of Vendors Identity Cards,	2 set of hard copies, along with all details & 2 set of soft	End of Week 8

	linkage with Aadhar no. of the vendors and GIS mapping of the existing Vendors.	copies	
3	Draft City Street Vending Plan submission to CMMU/DUDA	2 hard copies & 2 set of soft copies	End of Week 22
4	Final City Street Vending Plan submission for approval by State Level Project Sanction Committee (with recommendation of TVC & ULB board)	3 hard copies & 3 set of soft copies	End of Week 26
5	Draft Detailed Infrastructure Plan (DIP) submission for approval by State Level Project Sanction Committee (with recommendation of TVC/ULB)	2 hard copies & 2 set of soft copies	

Above given time schedule shall be strictly adhered to. In case of any delay City Project officer may consider time extension on the merits otherwise a penalty for delay at the rate of 0.25% of total payment per week shall be levied.

7. Experts and Inputs

Sr. No.	Expert Title	Qualifications and Skills	Experience
1	Team Leader/ Urban Development Specialist	<ul style="list-style-type: none"> • Masters or equivalent in planning/ engineering/economics/ other relevant disciplines • Sound knowledge of urban development issues 	Sector experience of more than 10 yrs and experience of project management of similar projects of at least 5 years
2	MIS expert	<ul style="list-style-type: none"> • Degree in Computer Science/MCA • Expertise in statistical analysis and software development/ MIS applications 	At least 5 years experience
3	Social Development Specialist	<ul style="list-style-type: none"> • Degree or equivalent in social development discipline • Sound understanding on issues of urban poor 	At least 5 years working experience with urban poor and community development
4	GIS expert	<ul style="list-style-type: none"> • Masters or equivalent degree in Geo-informatics • Knowledge and experience in GIS mapping 	At least 5 years experience
5	Project Engineer/ Infrastructure Specialist	<ul style="list-style-type: none"> • Degree in Civil Engineering • Sound knowledge of municipal services network, design norms, contracting 	At least 5 years experience in Project engineering.
6	Capacity Building /Training/Site Coordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelors/Masters in Urban Planning / Social science • Good understanding of surveys and experience in data collation and analysis • Good communication and networking skills 	5 years experience of working on urban projects.

The persons whose CVs are proposed in the bid shall not be allowed to change. In case of any urgency, City Project Officer/Project Officer, CMMU/DUDA may consider request of the bidder.

8 Working arrangements

8.1 Management and counterpart staff -

The assignment will be contracted by the City Project Officer CMMU. He will ensure the support of government officials, parastatal agencies wherever necessary.

8.2 Items to be provided by the Client

City Mission Management Unit/DUDA will:

- a. Designate an "Officer-in charge" responsible for management and coordination of consultants.
- b. Support in constitution of Town Vending Committee.
- c. Nominate officers from relevant sections of the agency to participate in the process of stakeholder consultation and CSVP preparation etc.
- d. Provide the Consultant with existing maps (as available with it) and data on Corporation and service delivery.
- e. Provide the Consultant with necessary authorization to procure information from line departments.

8.3 Consultant will be responsible to:

- a. Arrange its own office space and equipment, surveys
- b. Arrange for all transportation and travelling required
- c. Arrange its own translations, communication, data processing, and printing equipment and necessary stationeries
- d. Work closely with the officer-In charge and the Corporation.

9. Payment Schedule

All payments shall be made at the City level after verification by the District Magistrate and the Project Officer.

Sr. No.	Deliverable	Percentage of payment
1	Submission of Inception report within 2 week of agreement, Conduct of Survey for Identification and enlisting of Street Vendors, Bio-metric survey, collecting of mobile no. of vendors, capturing photographs, preparation of Vendors Registration Certificates & Identity Cards, linkage with Aadhar no. of the vendors and GIS mapping of the existing Vendors.	50% of the total fees
2	Draft City Street Vending Plan submission to CMMU/DUDA	10% of the total fees
3	Final City Street Vending Plan submission for approval by State Level Project Sanction Committee (with recommendation of TVC & ULB board)	20% of the total fees
4	Draft Detailed Infrastructure Plan (DIP) submission for approval by State Level Project Sanction Committee (with recommendation of TVC/ULB)	
5	After approval of Detailed Infrastructure Plans (DIPs) by State Level Project Sanctioning Committee of SULM, UP	20% of the total fees

Performance Security Form (Bank Guarantee)

In consideration of the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called "The Government") having agreed to exempt _____ (hereinafter called "The said Consultant") from the demand, under the terms and conditions of an Agreement dated _____ made between _____ and _____ for _____ (hereinafter called the "The said Agreement") of security deposit for the due fulfilments by the said Consultant(s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for Rs. _____ (Rupees _____ only), we, _____ (hereinafter referred to as "The Bank") at the request of (indicate the name of the bank) Consultant(s) do hereby undertake to pay to the Government an amount not exceeding Rs. _____ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Government by reason of any breach by the said Consultant (s) of any of the terms and conditions contained in the said Agreement

We _____ do hereby undertake to pay the (indicate the name of the Bank) amounts demur payable under this Guarantee without any demur merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is due by way of loss or damages caused to or would be caused to or suffered by the Government by reason of any breach by the said Consultant(s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reason of the Consultant(s) failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this Guarantee. However, our liability under this Guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. _____

3. We undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Consultant(s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this Bond shall be valid discharge of our liability for payment there under the Consultant(s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We _____ further agree that the guarantee (indicate the name of Bank) herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till _____ (Office/Department), Ministry of _____ certified that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Consultant(s) and accordingly discharges the Guarantee. Unless a demand or claim under this Guarantee is made on us in writing on or before the _____, we shall be discharged from all liability under this Guarantee thereafter.

5. We _____ further agree with the Government (indicate the name of Bank) the Government that the Government shall have the fullest liberty

without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extent time of performance by the said Consultant(s) from time-to-time any of the powers exercisable by the Government against the said Consultant(s) and to forbear or enforce any of terms and conditions relating to the said Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said Consultant(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Consultant(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have effect of so relieving us.

6. This Guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Consultant(s).

7. We _____, lastly undertake not to revoke (indicate the name of Bank) this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing. Dated the _____ day of 2018 for _____ (indicate the name of Bank)

Note 1:- The stamp papers of appropriate value shall be purchased in the name of bank that issues the": Bank Guarantee"

Note 2:- The Bank Guarantee will be accepted which is issued by State Bank of India or its subsidiaries or any Indian Nationalized Bank or any Indian Nationalized Bank.